प्रारम्भ हो कर कलकत्ता जाने के लिए अलग से ट्रेन सेवा उपलब्ध है किन्तु भिलाई से कलकत्ता के लिए सीधी ट्रेन सेवा अभी तक प्रारम्भ नहीं की जा सकी है। वैगन अलाटमेंट की इनवर्ड-आऊटवर्ड नीति के कारण बिलासपुर डिवीज़न में सदैव रेल वैगनों का संकट बना रहता है।

महोदय, फिर सर्वाधिक आय देने वाला बिलासपुर डिवीज़न रोज़गार, उद्योग, यात्री सुविधायें. .

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): ज्यादा लम्बा है तो दे दीजिये, मैं रिकार्ड का पार्ट बनवा दूंगा।

श्री गोविन्दराम मिरी: एक मिनट। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं बिलासपुर में रेलवे का दसवां ज़ोन प्रारम्भ करने की अविलम्ब घोषणा करें। धन्यवाद।

Railway network development in Orissa

SHRI SARADA MOHANTY (Orrisa): Mr. Vice-Chairman, Sir, though the State of Orissa is rich in iron ores, coal, forest products and other important minerals but due to lack of Railway network development, these natural resources could not be explored. Due to this, the State of Orissa could not develop and remains backward in comparison to other States of the country. To make the State develop, the people of Orissa as well as the Government of Orissa, moved the Central Government and specially the Ministry of Railways times without number to develop the railway network in the State for exploration of minerals and forest products.

Sir, in recent years, some projects for laying railway lines in the backward and tribal areas of the State have been sanctioned by the Planning Commission, and the Ministry of Railways made Budgetary provisions for new lines, and the survey has been conducted. But I am sorry to say that the new railway lines from Jakhpura to Bansapani and Talcher to Sambalpur could not materialise due to redtapism of the officials of the Ministry of Railways. It will not be out of place to mention here that in the 1993-94 Railway Budget, a sum of Rs. 25 crores was provided but could not be spent for the construction of the Railway line due to redtapism of the Railway officials, and it was diverted to other works. This kind of things are happening in the case of new railway lines in the State of Orissa.

In order to speed up the work of new railway lines and other railway works in the State, last year the Chief Administrative/Construction office of the South Eastern Railway was shifted to Bhubaneswar from its head office at Calcutta. The State Government of Orissa provided 300 quarters for accommodating the office and the staff. But I am sorry to say that this office is not functioning practically, and now it is heard that this office will be back to the bowler, that is, it will be shifted back to the headquarters at Calcutta. If it is done, development of the railway network in the tribal and backward areas of the State will be in doldrums. The above mentioned two new railway lines are project-oriented and are proposed to be completed within the Eighth Plan period.

Sir, the main aim for shifting the Construction office to Bhubaneswar was for speedy monitoring of the railway network development in the State of Orissa. If this office is shifted to Calcutta, then the railway line development work in Orissa will be seriously hampered.

Hence, I urge upon the Railway Minister, through you, Sir, not to shift the office of the Chief Administrative Construction from Bhubaneswar to Calcutta and also to complete the new lines such as the Daitan-Banaspani and Talcher-Sambalpur within the Eighth Plan period and to expedite the Bolangir-Khurda Road and Lanjigarh-Junagarh new railway lines. Thank you, Sir.

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa): Sir, I associate myself with this Special Mention.

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): श्री चतुरानन मिश्र, आप तो बहुत ही अनुभवी, पुराने और

सीनियर सदस्य हैं जो लम्बे-लम्बे वक्तव्य यहां स्पेशल मेंशन में पढ़े जाते है।

श्री चतुरानन मिश्र: आप तो पहले ही कह रहे हैं। पहले कहिएगा या बाद में। आप बाद में कह देते।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): मैं आपको नहीं कह रहा हूं मैं केवल अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता कि इसमें जो समय लगता है वह सब्जेक्ट इंट्रोड्यूज कर दें, उसकी कापी यहां दे दें। वह रिकार्ड का पार्ट हो जाये। कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता। आगे के लिए पूछ रहा हूं अभी आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं।

श्री हेच० हनुमनतप्पा: आप डिसिप्लिन करना चाहते हैं वह ठीक है। यह डिसिप्लिन हर आइटम पर होना चाहिए। वह डिसिप्लन हम खो बैठे हैं...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): वह आप सुबह बात कीजिएगा मिश्रा जी को बोलने दीजिए।

Pollution in Amjhore Rohtas District, Bihar, due to effluent discharge by P.P.C.L. Project

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): वह बात ठीक है। दो मिनट में आमतौर पर लोगों को खत्म करना चाहिए और अगर नहीं करते हैं तो बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में इस पर विचार करके एसोसिएट करने के लिए रिटर्न की बात कर लीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): वह हो जाये तो अच्छा रहेगा।

श्री चतुरानन मिश्र: मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये आपका ध्यान बिहार के रोहतास जिले में अमझोर नाम की जगह में एक गंधक के कारखाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो भारत सरकार का है — पी०पी०सी०एल०। उस कारखाने से दूषित पानी निकलता है जिससे 12 गांवों के लोग तबाह हो गये हैं। कुछ गांवों के नाम हैं - नाबादी, खेलाबाद, करमा, कोठी बगहा, मेहरान और अन्य दूसरे गांव। यह पानी इतना दूषित है कि पूरी जमीन ऊसर हो गयी है। जो मवेशी पी लेते हैं उस पानी को या तो मर जाते हैं या अगर उनके पेट में बच्चा रहता है तो गर्भपात हो जाता है। किसान बहुत ज्यादा तबाह है। यह सरकारकृत विपत्ति है। इसीलिए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि अविलम्ब हस्तेक्षप करके उन किसानों के दुख को दूर करे। धन्यवाद। देखिए, हमने ज्यादा टाइम नहीं लिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): मैं आपको इसमें नहीं कह रहा था। केवल एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि जब पढ़ना ही है तो रिकार्ड का पार्ट बना देते हैं और वह विषय इंट्रोड्यूस कर दें तो रेडियो और टी०वी० पर जो आना है वह आ जायेगा और अगर प्रेस को देना है तो रिलीज कर सकते हैं। It will save time so that we can devote more time to real debate.

श्री चतुरानन मिश्र: सुझाव अच्छा है आपका। इसको बैठकर तय करेंगे।

उपसभाध्यक्ष: ठीक है। संघ प्रिय गौतम।

Representation of S.C./ST Officers in I.A.S. from State Civil Services in Uttar Pradesh

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, देश के अनेकों राज्यों में गरिमामय पदों की नियुक्तियों और प्रोन्नतियों में पी०सी०एस० और आई०ए०एस० अधिकारियों में प्रायः एक विवाद चला रहता है। हमारे उत्तर प्रदेश में प्रोन्नतियों में 33 प्रतिशत पद तो भरे जाते हैं पी०सी०एस० अधिकारियों से और सीधी भर्ती से जो आई०ए०एस० आते हैं, 67 प्रतिशत उनसे भरे जाते हैं। प्रायः पी०सी०एस० अधिकारियों की शिकायत रही है कि प्रोन्नतियों में और गरिमामय पदों की नियुक्तियों में पी०सी०एस० अधिकारियों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। आये दिन अखबारों में पढ़ने, सुनने और देखने को भी मिलता है। लेकिन कोढ़ में खाज वाली कहावत यह है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह से प्रोन्नतियों से भरे जाने वाले पद जो पी०सी०एस० या राज्य की अन्य सेवाओं से भरे जाते हैं, वे 123 चिन्हित पद हैं। पर बड़े ही दुख की बात यह है कि इनमें से एक भी पद आज तक किसी भी अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारियों से नहीं भरा गया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में प्रायः अब तक जितनी सरकारें बनी हैं वे अपने को समाजवादी सरकारें कहती हैं और इन वर्गों का हितैषी कहती है लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक 123 पदों में से एक भी पद अनुसूचित जाति के पी०सी०एस० या राज्य की अन्य सेवाओं के अधिकारियों से नहीं भरा गया है।